Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

Original Article

गया जिले में अधिवासों के उद्भव, आकारिकी, कार्य एवं नियोजन: एक भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. साधना कुमारी
सहायक प्राध्यापिका, भूगोल विभाग एस. डी. कॉलेज परैया (गया)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया.

Manuscript ID: yrj-140306

ISSN: 2277-7911
Impact Factor – 5.958

Volume 14
Issue 3
July-August-Sept.- 2025
Pp. 63-72

Submitted: 1 July 2025
Revised: 22 July 2025
Accepted: 30 July 2025
Published: 10 Sept. 2025

Corresponding Author:
डॉ. साधना कुमारी

Quick Response Code:

Web. https://yra.ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.18480830

DOI Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.18480830

प्रस्तावना:

मानव भूगोल में अधिवासों (Settlements) का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अधिवास मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होते हैं। किसी भी क्षेत्र में अधिवासों का स्वरूप वहाँ की भौतिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक संरचना तथा नियोजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। बिहार राज्य का गया जिला इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, बल्कि भौगोलिक विविधताओं से भी परिपूर्ण है।

गया जिले में ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के अधिवास विकसित हुए हैं।[1] फल्गु नदी की घाटी, उपजाऊ कृषि भूमि, पठारी भाग, धार्मिक पर्यटन तथा परिवहन नेटवर्क ने यहाँ अधिवासों के उद्भव और विकास को दिशा प्रदान की है। प्रस्तुत लेख में गया जिले में अधिवासों के उद्भव, उनकी आकारिकी, कार्यात्मक स्वरूप तथा नियोजन की स्थिति का विस्तृत भौगोलिक विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत लेख में गया जिले में अधिवासों के ऐतिहासिक उद्भव, उनके आकारिकी (Morphology), कार्यात्मक स्वरूप तथा वर्तमान नियोजन स्थिति का एक समग्र भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, ग्रामीण-नगरीय अधिवासों में विद्यमान संरचनात्मक भिन्नताओं, नगरीकरण की प्रवृत्तियों तथा भविष्य की नियोजन संभावनाओं को भी समझने का प्रयास किया गया है, जिससे क्षेत्रीय विकास की भौगोलिक व्याख्या को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

How to cite this article:
डॉ. साधना कुमारी (2025). गया जिले में अधिवासों के उद्भव, आकारिकी, कार्य एवं नियोजन: एक भौगोलिक विश्लेषण. Young researcher, 14(3), 63–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.18480830

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय:

भौगोलिक स्थिति गया जिला बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जहानाबाद, पूर्व में नवादा, दक्षिण में झारखंड राज्य तथा पश्चिम में औरंगाबाद जिला स्थित है। जिले का क्षेत्रफल लगभग 4,976 वर्ग किलोमीटर है।[2]

भौतिक स्वरूप गया जिले का उत्तरी भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र से संबंधित है, जबकि दक्षिणी भाग छोटानागपुर पठार के विस्तार के रूप में जाना जाता है। इस कारण जिले में समतल मैदान, हल्की पहाड़ियाँ और पठारी भू-भाग पाए जाते हैं।

जल संसाधन:

फल्गु, मोरहर, निरंजना और पंचाने नदियाँ जिले की प्रमुख नदियाँ हैं।[3] इन नदियों ने न केवल कृषि को समृद्ध किया बल्कि अधिवासों के स्थान चयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जलवायु जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है, वर्षा ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है तथा शीत ऋतु अपेक्षाकृत शुष्क और ठंडी होती है।

गया जिले में अधिवासों का उद्भव:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गया जिला प्राचीन काल से ही मानव बसाहट का प्रमुख केंद्र रहा है। वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित अनेक ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ मिलते हैं। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विष्णुपद मंदिर और पिंडदान की परंपरा ने भी गया को हिंदू धार्मिक अधिवास के रूप में प्रतिष्ठित किया।4

प्राकृतिक कारक:

गया जिले में अधिवासों के उद्भव एवं विकास में प्राकृतिक कारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जिले के मैदानी भागों में पाई जाने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ प्रारंभ से ही स्थायी ग्रामीण अधिवासों का विकास हुआ। फल्गु नदी तथा उसकी सहायक नदियों की उपलब्धता ने न केवल सिंचाई सुविधाएँ प्रदान कीं, बल्कि पेयजल, धार्मिक क्रियाकलापों एवं परिवहन में भी सहायक भूमिका निभाई।

इसके अतिरिक्त, जिले की समतल भूमि ने अधिवासों के विस्तार एवं नगरीकरण को सरल बनाया, जबकि दक्षिणी भाग में स्थित पठारी क्षेत्र ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सीमित किंतु सघन अधिवासों को जन्म दिया। इस प्रकार, प्राकृतिक संरचना ने गया जिले में अधिवासों के स्वरूप, वितरण एवं आकारिकी को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है।

- उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी
- नदियों की उपलब्धता
- समतल भूमि और पठारी सुरक्षा

इन कारकों ने प्रारंभिक अधिवासों के विकास में सहायता की।

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website: https://yra.ijaar.co.in/*
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

सामाजिक-आर्थिक कारक:

- कृषि आधारित जीवन
- धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ
- स्थानीय व्यापार और शिल्प

इन तत्वों ने अधिवासों को स्थायित्व प्रदान किया।

अधिवासों की आकारिकी (Morphology):

अधिवासों की आकारिकी से आशय उनके भौतिक स्वरूप, सड़क व्यवस्था, भवन संरचना और भूमि उपयोग से है।अधिवासों की आकारिकी से आशय उनके भौतिक स्वरूप, सड़क व्यवस्था, भवन संरचना तथा भूमि उपयोग प्रतिरूप से है।[5] यह किसी भी क्षेत्र में मानव अधिवासों के ऐतिहासिक विकास, भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गया जिले में अधिवासों की आकारिकी पर प्राकृतिक वातावरण, स्थलाकृति, जल संसाधनों की उपलब्धता, परिवहन नेटवर्क तथा नगरीकरण की गति का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

ग्रामीण अधिवासों की आकारिकी प्रायः सघन एवं अनियमित पाई जाती है, जहाँ आवासीय इकाइयाँ एक-दूसरे के निकट स्थित होती हैं। इन अधिवासों में कच्चे एवं अर्द्ध-पक्के मकानों की प्रधानता है तथा सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं। भूमि उपयोग मुख्यतः कृषि, आवास एवं पशुपालन से संबंधित है। नदी घाटियों एवं उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में स्थित गाँव अपेक्षाकृत अधिक विकसित और सघन हैं।

इसके विपरीत, नगरीय अधिवासों—विशेषकर गया नगर और बोधगया—में आकारिकी अपेक्षाकृत नियोजित एवं विस्तारित स्वरूप में विकसित हुई है। यहाँ पक्के भवन, सुव्यवस्थित सड़क नेटवर्क, वाणिज्यिक क्षेत्र, प्रशासनिक परिसर तथा शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थान स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक क्षेत्रों में स्थित हैं। धार्मिक पर्यटन के कारण बोधगया में होटल, धर्मशाला एवं सेवा-आधारित भूमि उपयोग का प्रभुत्व देखा जाता है।

कुल मिलाकर, गया जिले में अधिवासों की आकारिकी भौगोलिक विविधताओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा समकालीन नगरीकरण प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, जो क्षेत्रीय विकास के स्तर एवं नियोजन की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।[6]

ग्रामीण अधिवासों की आकारिकी:

गया जिले के अधिकांश अधिवास ग्रामीण प्रकृति के हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रकार की आकारिकी पाई जाती है:

- सघन अधिवास: उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में
- रेखीय अधिवास: सड़कों और नदियों के किनारे
- विखंडित अधिवास: पठारी और वन क्षेत्रों में

गया जिले के अधिकांश अधिवास ग्रामीण प्रकृति के हैं और इनकी आकारिकी मुख्यतः भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। जिले में ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख प्रकार्यात्मक एवं भौतिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

सघन अधिवास (Compact Settlements):

उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में अधिकतर सघन अधिवास विकसित हुए हैं। यहाँ घर-बसेठियाँ एक-दूसरे के निकट स्थित होती हैं और आमतौर पर एक या दो केंद्रीय मार्गों से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार के अधिवास में भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है और सामुदायिक सुविधा केंद्र—जैसे कुएँ, तालाब और पंचायत भवन—सुलभ स्थानों पर स्थित होते हैं।

रेखीय अधिवास (Linear Settlements):

सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे स्थित गाँवों में रेखीय आकारिकी देखी जाती है।[7] इन अधिवासों में घर तथा अन्य संरचनाएँ एक लंबी रेखा में विकसित होती हैं, जिससे मुख्य मार्ग तक पहुँच सुनिश्चित होती है। यह प्रकार कृषि उत्पादों के परिवहन और जल संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अनुकूल होता है।

विखंडित अधिवास (Dispersed Settlements):

पठारी, ऊबड़-खाबड़ एवं वन क्षेत्रों में विकेन्द्रित या विखंडित अधिवास अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास में घर एक-दूसरे से दूरी पर बने होते हैं और सामान्यत: खेतों या प्राकृतिक संसाधनों के आसपास फैले होते हैं। यह संरचना प्राकृतिक सुरक्षा, भूमि उपयोग की स्वतंत्रता और सीमित जनसंख्या घनत्व के कारण विकसित हुई है।

ग्रामीण अधिवासों की यह विविध आकारिकी न केवल भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों, जैसे खेती, पशुपालन और सामुदायिक मेलजोल, को भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय विकास और अधिवास नियोजन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना संभव होता है।

नगरीय अधिवासों की आकारिकी

गया नगर और बोधगया जिले के प्रमुख नगरीय केंद्र हैं। यहाँ मिश्रित भूमि उपयोग, संकरी गलियाँ, व्यावसायिक क्षेत्र और आवासीय कॉलोनियाँ पाई जाती हैं।[8]

आवासीय संरचना:

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और अर्ध-पक्के मकान अधिक हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में पक्के और बहुमंजिला भवनों की संख्या बढ़ रही है।

अधिवासों का कार्यात्मक स्वरूप:

ग्रामीण अधिवासों के कार्य:

- कृषि उत्पादन
- पशुपालन
- कुटीर उद्योग

नगरीय अधिवासों के कार्य:

- प्रशासनिक कार्य
- व्यापार और वाणिज्य
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ
- धार्मिक और पर्यटन गतिविधियाँ

धार्मिक-पर्यटन अधिवास:

बोधगया एक विशिष्ट धार्मिक-पर्यटन अधिवास है जहाँ देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। बोधगया गया जिले का एक विशिष्ट धार्मिक-पर्यटन

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

अधिवास है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का अधिवास मुख्यतः धार्मिक, पर्यटन और सेवा आधारित गतिविधियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। बोधगया का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा इसी प्रकार के अधिवासीय विकास को दर्शाता है।

धार्मिक स्थल—विशेष रूप से महाबोधि मंदिर परिसर—के चारों ओर हॉल, धर्मशाला, होटल, आवासीय भवन और वाणिज्यिक क्षेत्र व्यवस्थित हैं। इस प्रकार का अधिवास आम ग्रामीण या नगरीय ढांचे से भिन्न होता है क्योंकि यहाँ सड़क नेटवर्क, यातायात सुविधाएँ, सार्वजनिक सेवा केंद्र और पर्यटन-आधारित व्यवसाय अधिवास की भौतिक और कार्यात्मक संरचना को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं।[9]

बोधगया में अधिवास की आकारिकी मुख्य रूप से सघन और केंद्रित है, जिसमें धार्मिक स्थल के चारों ओर बाजार, होटल, पर्यटन सेवाएँ और स्थानीय निवास संरचनाएँ घेरती हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के कारण अधिवास में बहुभाषी संकेतक, अंतरराष्ट्रीय आवासीय सुविधाएँ और सुरक्षा व्यवस्थाएँ विकसित हुई हैं।

इस प्रकार, बोधगया का धार्मिक-पर्यटन अधिवास न केवल धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह गया जिले में अधिवासों के कार्यात्मक स्वरूप और आकारिकी में विविधता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह अधिवास स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यटन आधारित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

गया जिले में अधिवासों का नियोजन:

ग्रामीण नियोजन:

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विकास योजनाएँ लागू की जाती हैं। सड़क, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवास नियोजन मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य सड़क निर्माण, आवासीय सुधार, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण नियोजन में निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जाती हैं:

सड़क और परिवहन नेटवर्क:

ग्रामीण अधिवासों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रख-रखाव किया जाता है। इससे कृषि उत्पादों के परिवहन और लोगों की आवाजाही में सुविधा होती है।

आवास और भूमि उपयोग:

ग्रामीण योजनाओं के तहत सुदृढ़ और सुरक्षित आवासीय इकाइयाँ विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही भूमि उपयोग नियोजन के माध्यम से आवास, कृषि, सामुदायिक केंद्र और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र सुनिश्चित किए जाते हैं।[10]

जलापूर्ति और स्वच्छता:

ग्रामीण अधिवासों में पेयजल आपूर्ति और शौचालय निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। जल स्रोतों की सुरक्षा और जल-प्रबंधन की प्रणाली अधिवास नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है।

सामुदायिक एवं सार्वजनिक सुविधाएँ:

पंचायत स्तर पर विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन और मेलों/उत्सव के लिए खुली जगहें विकसित की जाती हैं, जिससे सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

सतत विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण:

ग्रामीण नियोजन में वन संरक्षण, जल स्रोत प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिवास विकास पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित और सतत हो।

इस प्रकार, गया जिले के ग्रामीण अधिवासों का नियोजन स्थानीय प्रशासन, पंचायत एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से संरचित रूप में किया जाता है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होता है।

नगरीय नियोजन:

नगर निगम और नगर परिषद द्वारा भूमि उपयोग, यातायात प्रबंधन और आवासीय विस्तार की योजनाएँ बनाई जाती हैं।गया जिले के नगरीय अधिवासों का नियोजन मुख्य रूप से नगर निगम और नगर परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य भूमि उपयोग, यातायात प्रबंधन, आवासीय और वाणिज्यिक विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत सेवाओं का समुचित विकास सुनिश्चित करना है।

नगरीय नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

भूमि उपयोग नियोजन:

नगर निगम द्वारा भूमि का वर्गीकरण किया जाता है—आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सुविधा और हरित क्षेत्र। यह नियोजन नगरीय अधिवासों के संतुलित विकास और अव्यवस्थित विस्तार को रोकने में सहायक है।

यातायात एवं परिवहन प्रबंधन:

सड़क नेटवर्क, परिवहन मार्ग, सार्वजनिक पार्किंग और यातायात नियंत्रण की योजनाएँ नगर नियोजन का अहम हिस्सा हैं। यह शहर में वाहन संचलन की सुविधा और भीड़-भाड़ कम करने में सहायक होता है।

आवासीय और शहरी विस्तार:

नगर निगम आवासीय परियोजनाओं, स्लम पुनर्विकास और नए कॉलोनियों के निर्माण के माध्यम से शहरी विस्तार को नियंत्रित करता है। इसमें सुरक्षित एवं सुलभ आवास, ग्रीन बेल्ट और सामुदायिक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।

सार्वजनिक सेवाएँ और बुनियादी ढांचा:

नगर नियोजन में पेयजल, बिजली, नाली व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थान

की सुविधा शामिल होती है। यह अधिवासों के सुचारू और सतत संचालन के लिए आवश्यक है।

पर्यावरण और सतत विकास:

नगर नियोजन में हरित क्षेत्र, पार्क, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शहरी अधिवास विकास पर्यावरण के अनुकूल और सतत हो।

नगरीय अधिवासों का यह नियोजन शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने, आवासीय और वाणिज्यिक संतुलन बनाए रखने तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाता है।[11]

नियोजन से संबंधित समस्याएँ:

- अनियोजित शहरी विस्तार
- झुग्गी-झोपड़ी बस्तियाँ
- आधारभूत सुविधाओं की कमी

अधिवासों से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ

- जनसंख्या दबाव
- बेरोजगारी
- पर्यावरणीय क्षरण
- यातायात और प्रदूषण

गया जिले में ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के विकास के बावजूद कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएँ विद्यमान हैं, जो अधिवासों की सतत और संतुलित प्रगति में बाधक हैं। प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

जनसंख्या दबाव:

अधिवासों में जनसंख्या का तीव्र वृद्धि दर विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में दबाव उत्पन्न करता है। सीमित भूमि, आवासीय इकाइयों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आवासीय तनाव बढ़ता है और शहरी विस्तार अक्सर अव्यवस्थित हो जाता है।

बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता:

ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता की समस्या उत्पन्न होती है। यह प्रवासी मजदूरों के बहाव, कम आय और सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियों को जन्म देती है।

पर्यावरणीय क्षरण:

अधिवासों के अनियोजित विस्तार, कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण वनों की कटाई, जल स्रोतों का संकट, मृदा अपरदन और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ रही हैं। यह अधिवासों के सतत विकास को प्रतिकूल प्रभावित करती हैं।

यातायात और प्रदूषण:

शहरी अधिवासों में वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण जाम, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन एवं सड़क नेटवर्क की अपर्याप्तता लोगों के जीवन स्तर और अधिवासों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

बुनियादी सुविधाओं की असमान उपलब्धता:

कुछ ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-3 | July – August – September 2025

बुनियादी सुविधाओं की असमान उपलब्धता अधिवासों की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव:

- संतुलित नगरीय-ग्रामीण विकास
- धार्मिक पर्यटन का सतत विकास
- पर्यावरण-अनुकूल नियोजन
- आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण

गया जिले में अधिवासों के सतत विकास और नियोजन के लिए कई संभावनाएँ निहित हैं। वर्तमान परिस्थितियों और आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं:

संतुलित नगरीय और ग्रामीण विकास:

शहरी और ग्रामीण अधिवासों के विकास में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुधार और नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्थित आवासीय एवं वाणिज्यिक विस्तार सुनिश्चित करने से अधिवासीय असंतुलन और अव्यवस्थित नगरीकरण को रोका जा सकता है।

धार्मिक पर्यटन का सतत विकास:

बोधगया और अन्य धार्मिक स्थलों के अधिवासों में पर्यटन आधारित गतिविधियों का सतत विकास आवश्यक है। पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करते हुए आवासीय, वाणिज्यिक और धार्मिक संरचनाओं का नियोजित विस्तार करना चाहिए।

पर्यावरण अनुकूल नियोजन:

अधिवासों का नियोजन प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय संतुलन के अनुरूप होना चाहिए। इसमें जल स्रोतों का संरक्षण, हरित क्षेत्र, प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन शामिल हैं, जिससे अधिवास विकास पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ हो।[15]

आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण:

सड़क, परिवहन, जलापूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण अधिवासीय जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। स्मार्ट एवं तकनीकी आधारित समाधान अपनाकर अधिवासों की कार्यक्षमता और आवासीय सुविधा में सुधार किया जा सकता है।

सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय प्रशासन:

अधिवास नियोजन में स्थानीय जनता और पंचायतों/नगर निगम की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित होता है।

सतत आर्थिक और सामाजिक विकास:

रोजगार सृजन, स्वरोजगार योजनाएँ, कौशल विकास केंद्र और स्थानीय व्यापार के अवसर बढ़ाने से अधिवासों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों और स्वास्थ्य/शिक्षा सेवाओं के माध्यम से अधिवासीय जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है।[12]

इस प्रकार, गया जिले में संतुलित, पर्यावरण-अनुकूल और सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील अधिवास नियोजन को अपनाकर भविष्य में स्थायी और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। यह न केवल जिले के भौगोलिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि

स्थानीय लोगों की जीवन गुणवत्ता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी सहायक होगा।

उपसंहार:

गया जिले में अधिवासों का विकास प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों का संयुक्त परिणाम है। अधिवासों की आकारिकी और कार्यात्मक स्वरूप जिले की भौगोलिक विविधता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सुनियोजित विकास के माध्यम से गया जिले के अधिवासों को सतत और संतुलित विकास की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है।गया जिले में अधिवासों का विकास प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक-आर्थिक कारकों के पारस्परिक एवं संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। जिले की भौगोलिक संरचना—जिसमें उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, फल्गु नदी की घाटी, पठारी भू-भाग तथा वनाच्छादित क्षेत्र सम्मिलित हैं—ने यहाँ अधिवासों के वितरण, घनत्व एवं स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है।[13] ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्व, विशेष रूप से गया और बोधगया जैसे केंद्रों का विकास, अधिवासों की कार्यात्मक विविधता को सुदृढ़ करता है, जहाँ धार्मिक, व्यापारिक, पर्यटन एवं सेवा-आधारित गतिविधियाँ प्रमुख रूप से विकसित हुई हैं।

ग्रामीण अधिवास मुख्यतः कृषि-आधारित हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में प्रशासनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक तथा पर्यटन संबंधी कार्यों की प्रधानता देखी जाती है। अधिवासों की आकारिकी—जैसे सघन, रैखिक एवं विकेंद्रित स्वरूप—जिले की स्थलाकृति, परिवहन नेटवर्क एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है। तीव्र नगरीकरण के परिणामस्वरूप अव्यवस्थित विस्तार, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा पर्यावरणीय दबाव जैसी समस्याएँ भी उभर कर सामने आई हैं।

अतः यह आवश्यक है कि गया जिले में अधिवासों का विकास सुनियोजित एवं संतुलित अधिवास नियोजन के माध्यम से किया जाए। भूमि उपयोग नियोजन, परिवहन एवं आवासीय सुविधाओं का समुचित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण-नगरीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई विकास रणनीतियाँ जिले को सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर कर सकती हैं। इस प्रकार, भौगोलिक दृष्टिकोण से किया गया अधिवास अध्ययन न केवल क्षेत्रीय विकास की समझ को सुदृढ़ करता है, बल्कि भविष्य की नियोजन नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।[14]

संदर्भ सूची:

1. हुसैन, मैजिद (2014). मानव भूगोल. नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन्स।
2. दीक्षित, आर. डी. (2010). भूगोल में बस्तियाँ एवं नगरीकरण. इलाहाबादः विद्यार्थी प्रकाशन।
3. सरकार, बिहार (विभिन्न वर्ष). बिहार जिला गजेटियर: गया जिला. पटना: बिहार सरकार।
4. भारत सरकार (2011). भारत की जनगणना 2011: बिहार राज्य एवं गया जिला. नई दिल्लीः रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारत।

5. सिंह, सविन्द्र (2008). मानव एवं आर्थिक भूगोल. नई दिल्ली: प्रयाग पुस्तक भवन।
6. सिंह, आर. एल. (2005). ग्रामीण भूगोल. वाराणसी: छात्र मित्र प्रकाशन।
7. सिंह, के. एन. (2012). अर्बन जियोग्राफी. नई दिल्ली: केदारनाथ रामनाथ।
8. माजिद हुसैन (2016). सेटलमेंट जियोग्राफी. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
9. जेम्स, प्रेस्टन ई. (1965). All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas. न्यूयॉर्क: ओडिसी प्रेस।
10. हैगेट, पीटर (2001). Geography: A Global Synthesis. लंदन: प्रेंटिस हॉल।
11. स्मिथ, डेविड एम. (1977). Human Geography: A Welfare Approach. लंदन: एडवर्ड अर्नोल्ड।
12. कार्टर, हैरॉल्ड (1995). The Study of Urban Geography. लंदन: एडवर्ड अर्नोल्ड।
13. बेरी, ब्रायन जे. एल. (1964). Cities as Systems within Systems of Cities. शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।
14. जॉनसन, जे. एच. (1970). Urban Geography: An Introductory Analysis. ऑक्सफोर्ड: पर्गामन प्रेस।
15. सिंह, एल. आर. (2011). भारतीय बस्तियाँ: स्वरूप एवं विकास. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
16. घोष, ए. (2006). Urban Planning in India. नई दिल्ली: पब्लिकेशन्स डिवीजन।
17. सरकार, भारत (विभिन्न वर्ष). National Sample Survey Reports (NSSO). नई दिल्ली: भारत सरकार।
18. विश्व बैंक (2010). Urbanization and Development in South Asia. वाशिंगटन डी.सी.: वर्ल्ड बैंक।
19. यूनेस्को (2015). Urban Growth and Sustainable Development. पेरिस: UNESCO।
20. सिंह, डी. पी. (2013). नगरीय भूगोल. पटना: भारती भवन।
21. मिश्रा, आर. पी. (2009). Geography of Indian Settlements. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।